

चीनी एप्स पर प्रतबिंध

प्रलिमिस के लिये:

भारत और उसके पड़ोसी देशों की अवस्थति

मेन्स के लिये:

चीनी एप्स पर प्रतबिंध लगाने का आरथक प्रभाव, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत-चीन संबंध।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने 54 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतबिंध लगाने की सफिरशि की है, जिसमें लोकप्रथि गेम 'गरेना फ्री फायर' भी शामिल है, जो गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चित्ताओं को उत्पन्न करता है।

- वर्ष 2020 में सरकार ने टकिटॉक और चीन के अन्य लोकप्रथि लघु वीडियो एप पर भी प्रतबिंध लगा दिया।
- भारत में ऐसे एप्स पर प्रतबिंध लगाने का नियम न केवल एक भू-राजनीतिक कदम है, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार पैतरेबाज़ी भी है जिसका महत्वपूर्ण आरथक प्रभाव हो सकता है।
- इससे पहले यह देखा गया था कि वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, जिसमें चीन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रकिंगड आयात किया गया, जो भारत में चीनी सामानों, वशिष्ठ रूप से मशीनरी की एक शूखला की नियितर मांग को रेखांकित करता था।



नियम के लाभ:

- राष्ट्र के तकनीकी बाज़ार में सहायता:**
 - इन चीनी वेबसाइटों और अनुपरयोगों को भारतीय जनता के लिये प्रतबिंधित करने से हमारी घरेलू आईटी प्रतभित्रों को अवसर प्रदान करने तथा इंटरनेट उपयोगकरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
 - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सलिकिन वैली (US) तथा चीन की बड़ी टेक फ्रम भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर असमंजस्य में हैं, लेकिन भारत का ध्यान अपने देश के तकनीकी बाजार की बजाय आईटी सेवाओं के नियात पर ज़्यादा रहता है।
 - पैसवि डिप्लोमेसी पर अब कोई भरोसा नहीं:** इन एप्स पर प्रतबिंध लगाने से भारत की ओर से भी एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यह अब चीन की नियितर

एंड नेगोशिएट पॉलसी का शक्तिर नहीं होगा ।

- **लद्दाख में गतिरोध** जारी है ।
- **चीन की महत्वाकांक्षा को चोट पहुँचाना:** यह प्रतिबंध चीन के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक अरथात् 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बिना, को प्रभावित कर सकता है ।
- **दुनिया के बाकी हिस्सों में नविंतरण स्थापित करने के अपने प्रयासों में चीनी इंटरनेट उदयोग को आरटफिशिपिल इंटेलज़िंस एलगोरिदम के लिये एक प्रशक्षिण को जारी रखने हेतु भारत के 500 मलियन से अधिक नेटज़िन्स (Netizens) की आवश्यकता है ।**
- **डेटा के महत्व को पहचानना:** भारत द्वारा एप्स पर प्रतिबंध और दूरसंचार हार्डवेयर एवं मोबाइल हैंडसेट से संबंधित प्रतिबंधों पर विचार करना डेटा संग्रह एवं डिजिटल तकनीक के लिये मददगार साबित हो सकता है ।

नियम के विपक्ष में तरक़:

- **डेटा गोपनीयता चीनी एप्स तक सीमित नहीं:** हाल के दिनों में अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की ओरी करने और भारत से बाहर के सर्वरों तक पहुँचाने की रपिएट के बाद एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।
 - हालाँकि डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा चिता केवल चीनी एप्स तक ही सीमित नहीं है ।
- **चीन पर भारत की आरथकि नियमिता:** चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य है क्योंकि भारत कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के उत्पादों पर नियमित है ।
- **प्रतिस्थापन का अभाव:** 118 से अधिक चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने के बाद भारतीय तकनीकियों के माध्यम से अन्य वेबसाइटों और एप्लीकेशन द्वारा इस कमी को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया गया है । लेकिन यह चीनी वेबसाइटों और एप्लीकेशन के उपयोग को रोकने में सक्षम नहीं है ।

आगे की राह

- प्राथमिक स्तर की भारतीय आईटी फर्मों को दूसरों को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के बजाए देश में ही सेवाओं को प्रदान करना चाहिये ।
- चीनी तकनीक की अनुपस्थिति में भारतीय उद्यमियों को मौजूदा फर्मों द्वारा अब तक प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को प्रविरत्ति रूप में नहीं देखना चाहिये बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उन सेवाओं एवं उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जिनका देश भर में भारतीयों द्वारा रोजमरा उपयोग किया जाएगा ।
 - नेटज़िन्स को वभिन्न बाज़ारों में उपलब्ध समान सेवाएँ प्रदान करने का उद्देश्य काफी व्यापक है, वहीं हमारे देश में भाषायी क्षेत्रीय बाधाएँ भी मौजूद हैं ।
 - यह एक विशिष्ट प्रकार के छोटे बाज़ारों के विकास का अवसर प्रदान करता है, जहाँ स्थानीय समुदाय द्वारा स्थानीय लोगों के लिये उपलब्ध कराई गई विशिष्ट इंटरनेट सेवाएँ मौजूद होंगी ।
- नए डिजिटल उत्पादों के लिये मूलतः अतिकृतीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर लगातार बढ़ते बाज़ार में उभरने की योजना बनानी चाहिये ।
 - उदाहरण के लिये ऐसे एप विकसित किये जा सकते हैं, जो विशिष्ट बाज़ार मूलय, स्थानीय ट्रेन और बस मार्ग से संबंधित सूचना प्रदान करते हों या फरि गैर-पारंपरिक बैंकिंग एवं उधार, शक्षिषा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्गीकृत विज़िज़ापन आदि की अनुमति देते हों ।

स्रोतः द हट्टी